

1	2	3	4	5
			पौघ	क्षेत्र
25.	पश्चिम बंगाल . . .	303404.00	650.00	275.00
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	26585.50	70.00	1675.00
27	चण्डीगढ़ . . .	727.50	1.70	30.00
28.	दादर एवं नागर हवेली . . .	8349.50	20.00	420.00
29.	दमन और दीव . . .	202.00	1.25	40.00
30.	दिल्ली . . .	7913.15	50.75	825.00
31	लक्षद्वीप . . .	296.50	1.30	35.00
32	पण्डिचेरी . . .	2777.00	8.00	150.00
		8862837.65	25000.00	550000.00

जयपुर में टेलीफोन कनेक्शनों का खराब रहना

822 डा. अरार अहमद : क्या संचार मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विगत छ. महीनों से जयपुर में आधे से भी अधिक कनेक्शन खराब पड़े हुए हैं, यदि नहीं, तो क्या सरकार इनका पता लगाने का प्रयास करेगी तथा इस संबंध में दोषी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सजा देगी,

(ख) नवम्बर, 1990 के अन्त तक, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में सामान्य तथा ओ.वाई.टी. श्रेणियों के टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कुल

कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं और उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) राजस्थान तथा इसके विभिन्न बड़े नगरों में टेलीफोन सहायक समितियाँ का गठन कब से नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं और अब इनका कब तक गठन कर लिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नहीं। जयपुर में टेलीफोन की खराबियाँ नियंत्रण में हैं।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

स्थान	ओ.वाई.टी.	पंजीकृत गैर ओ.वाई.टी. में	कुल
जयपुर जिला . . .	2427	40007	42434
जोधपुर . . .	477	9947	10424
कोटा . . .	547	5276	5823
उदयपुर . . .	761	8077	8838
अजमेर . . .	289	3200	3480

ग्राठवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मौजूदा प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना, 31-3-1994 तक की अनुमानित मांग को पूरा करना, 1-4-1995 तक 5000 या इससे अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन देना है।

(ग) राजस्थान की दूरसंचार सलाहकार समिति और जयपुर की टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्यकाल क्रमशः 31-5-89 और 31-7-89 को समाप्त हो गया है। इन समितियों का शीघ्र ही पुनर्गठन कर दिया जायेगा।

राजस्थान में गांवों और कस्बों में संचार-जाल

823. डा० अब्दुल अहमद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने गांव और कस्बे संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, कितने गांव अब कस्बे ग्राठवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक संचार माध्यमों से जोड़ दिये जायेंगे और शेष गांवों तथा कस्बों को कब तक उक्त सुविधा प्रदान कर दिया जाने की संभावना है,

(ख) क्या 1994 तक राजस्थान के छोटे गांवों को भी तार एवं टेलीफोन सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव या योजना है, यदि हा, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्राइवेट कोरियर सेवाओं से डाक-व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा है या किसी डाकघर के बंद होने का कोई मामला नजर में आया है, क्या प्राइवेट कोरियर सेवाओं के नियंत्रण के संबंध में कानून बनाने का कोई विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री और संचार मंत्रालय में उपमंत्री (बी जय प्रकाश) : (क) 30-11-1990 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के 2467

634 'R.S.—8.

ग्रामों तथा सभी 201 म्युनिसिपल कस्बों को संचार नेटवर्क के साथ जोड़ दिया गया है।

यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो ग्राठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5100 ग्रामों को संचार नेटवर्क के साथ जोड़ने की योजना है। संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में, सन् 2000 तक प्रत्येक ग्राम में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) जी हां, उपर्युक्त (क) के अनुसार।

(ग) जी नहीं। निजी कोरियर सेवा से डाक प्रणाली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। निजी कोरियर सेवाओं को प्रचालन के कारण किसी डाकघर को बंद नहीं किया गया है। निजी कोरियर सेवाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है। विभाग कोरियरों को पर्याप्त प्रतिस्पर्धा प्रदान कर रहा है।

Waiting List of Telephone Connection in Delhi

824. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to provide telephone connections to registered persons in each category and clear entire waiting list;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any steps have been taken to implement the decision so far;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(e) by which time the entire waiting list will be cleared?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JAI PARKASH): (a) to (e) The draft Eighth Plan